

प्रेषक,

डॉ. भूपिन्दर कौर औलख,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम,

देहरादून।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग

देहरादून : दिनांक : 21 मार्च, 2016

विषय: प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार लाभार्थियों हेतु संचालित अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना को बैंकेबल बनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1056 दिनांक 15.02.2016 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त धनराशि से अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब परिवारों के बेरोजगार लाभार्थियों हेतु संचालित 'अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना' के अन्तर्गत दिए जाने वाले ऋण को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीयकृत बैंकों/सहकारी बैंकों/ग्रामीण बैंको से पोषणीय/बैंकेबल बनाते हुए, उक्त योजना के संचालन हेतु शासनादेश संख्या 771/XVII-1/2006-07(02)/2006 दिनांक 29.6.2006 द्वारा प्रख्यापित नियमावली को वर्तमान परिप्रेक्ष्य की आवश्यकतानुसार निम्नवत संशोधित किए जाने की श्री राज्यपाल, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : -

1. योजना से अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे सभी परिवार आच्छादित होंगे, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹ 81,000/- तक एवं शहरी क्षेत्र में ₹ 1,03,000/- तक हो।
2. योजनान्तर्गत ₹ 20हजार से ₹ 10लाख तक की लागत का ऋण उक्त आय सीमा के अन्तर्गत आने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार लाभार्थियों को दिया जायेगा जिसमें से योजना की लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम ₹ 2.50लाख अनुदान राशि, 15 प्रतिशत लाभार्थी अंश और अवशेष राशि बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।
3. योजना से न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 55 वर्ष आयुसीमा वाले लाभार्थी आच्छादित होंगे।
4. उक्त योजनान्तर्गत ऋण लाभार्थी को राष्ट्रीयकृत बैंकों/सहकारी बैंकों/ग्रामीण बैंको के माध्यम से दिया जायेगा जिस हेतु ऋण गृहीता द्वारा देय न्यूनतम ब्याज का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंको द्वारा किया जायेगा।

क्रमशः...

(Signature)

5. अनुदान की राशि बैंक इन्डेड होगी तथा लाभार्थी द्वारा सुचारू रूप से योजना के संचालन एवं शतप्रतिशत वसूली के उपरान्त उसके ऋण के अंतिम किश्तों में समायोजित की जायेगी।
6. लाभार्थी अंश स्वयं लाभार्थी द्वारा वहन किया जायेगा एवं अवशेष धनराशि बैंको द्वारा ऋण के रूप में होगी। ऋण की अदायगी ऋण वितरण अथवा परिसम्पत्ति सृजन, जो भी पहले हो, के एक माह पश्चात् प्रारम्भ होगी, जो मासिक किश्तों में होगी तथा अधिकतम सीमा पांच वर्ष होगी।
7. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास में विज्ञप्ति के माध्यम स्वरोजगार हेतु ऋण आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाएंगे।
8. स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन के लिये जनपद स्तर पर गठित समिति को निम्नवत पुनर्गठित किया जाता है : -
 - 1- मुख्य विकास अधिकारी - अध्यक्ष।
 - 2- जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक - सदस्य।
 - 3- महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र अथवा नामित सक्षम प्रतिनिधि - सदस्य।
 - 4- जिला समाज/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी (जैसा लागू हो) - सदस्य सचिव।
 - 5- जनपद में अल्पसंख्यकों की अधिक आबादी वाले दो समुदायों के 01-01 प्रतिनिधि, जिन्हें अधिकतम 02 वर्ष हेतु चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा - सदस्य।
9. योजना के बैंकेबल होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा निगम को मात्र 25 प्रतिशत अनुदान/सब्सिडी राशि ही बजट व्यवस्था कर अवमुक्त की जाएगी।
- 2- इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि के बाद पूर्व संदर्भित शासनादेश दिनांक 29.6.2006 को मात्र इस सीमा तक ही संशोधित समझा जाएगा तथा अन्य प्राविधान, शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 407(पी)/XXVII-3/2015-16 दिनांक 10 मार्च, 2016 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(डॉ. भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

क्रमशः...

संख्या : 165 (1)/XVII-3/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : -

1. निजी सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी/मा. अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. मण्डलायुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल, नैनीताल/पौड़ी।
7. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
11. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड
12. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
13. समस्त जिला समाज/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी), सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,



(बी. एस. बोरा)
उप सचिव।

